

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का योगदान

Nand Kishor Yadav

Research Scholar, University Deptt. of Economics, T.M. Bhagalpur University, Bhagalpur

शोध शारांश :-

एमएसएमई का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, खासकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न कर, आय को उत्पन्न करता है जो उस देश में गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध होता है। कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई भारत में सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। इसके अलावे यह प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के इको-सिस्टम को विकसित करने में भी सहायक होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में खासकर सकल घरेलू उत्पाद, कुल रोजगार और भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई के योगदान का अध्ययन करता है।

शब्द कुंजी : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, भारत की जीडीपी, रोजगार, निर्यात

विषय परिचय :-

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एमएसएमई क्षेत्रों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है— वृहत पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग धन्धे। सामान्यतया वृहत पैमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसके संगठन का पैमान भी काफी बड़ा होता है, ऐसे उद्योगों में खासकर पूंजी की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए भारी लौह व इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि आते हैं। वहीं लघु उद्योगों के अंतर्गत जैसे उद्योगों को शामिल किया जाता है, जिसका पैमाना अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा जिनमें पूंजी तथा श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। सुती करघा उद्योग, खादी उद्योग, उनी हस्त करघा उद्योग, रेशमी हस्तकरघा उद्योग, रस्सी बनाने के उद्योग आदि भारत के प्रमुख लघु उद्योग हैं। वहीं सूक्ष्म या कुटीर उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और घर के सदस्यों की सहायता से ही चलाये जाते हैं। इनमें कारीगरों की संख्या लगभग 10 से 15 होती है। दियासलाई उद्योग, तेल धानी उद्योग, धानकुटाई उद्योग, गूड़ व खड़सारी उद्योग आदि भारत में कुछ प्रमुख सूक्ष्म या कुटीर उद्योग हैं। भारत सरकार ने Small, micro and medium enterprises development act 2006 पारित कर 2 अक्टूबर 2006 को लघु उद्योगों को तीन कैटेगरी में विभाजित किया है :-

1. माइक्रो उपक्रम:-वे उपक्रम जिनमें प्लांट व मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो।
2. लघु उपक्रम:-वे उपक्रम जिनमें मशीनरी व प्लांट में निवेश 25 लाख रुपये से 5 करोड़ के बीच हो।
3. मध्यम उपक्रम:-वे उपक्रम जिनमें मशीनरी व प्लांट में निवेश 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ के बीच हो।

इनमें प्रथम दो श्रेणी के उपक्रम को एमएसई तथा तीनों श्रेणी के उपक्रम को एमएसएमई कहा जाता है।
01 जुलाई 2020 के आत्म निर्भर भारत योजना के तहत एमएसएमई को नये तरीके से परिभाषित किया गया है :-

तालिका-1

वर्गीकरण	निवेश	वार्षिक टर्नओवर
सूक्ष्म उद्योग	1 करोड़ रुपये तक	5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्योग	10 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
मध्यम उद्योग	50 करोड़ रुपये तक	250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

तालिका-1 में जिन उद्योगों में प्लांट व मशीनरी में निवेश एक करोड़ रुपये तक और सलाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है वे सूक्ष्म उद्योग तथा जिन उद्योगों में प्लांट व मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपये तक और सलाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है वे लघु उद्योग जिन उद्योगों में प्लांट व मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रुपये तक और सलाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये तक है वे मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखे गए हैं। 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के बड़े अवसर का निर्माण करता है। इसके अलावे एमएसएमई कृषि क्षेत्र में कार्य करनेवाले कामगारों को भी समाहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का सामाधान करने में सहायक होती है। इसके अलावे एमएसएमई वृहत उद्योगों के लिए भी पूरक उद्योग के रूप में काम करती है। वहीं एमएसएमई द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए पूरे इको-सिस्टम को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोध के उद्देश्य :-

1. भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान का अध्ययन करना।
2. भारत के कुल रोजगार में एमएसएमई के योगदान का अध्ययन करना।
3. भारत के कुल विदेशी व्यापार में एमएसएमई के योगदान का अध्ययन करना।
4. एमएसएमई के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

साहित्यिक अवलोकन :-

शैली व अन्य(2020): ने अपने अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के योगदान में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न करने के साथ-साथ गरीबी को कम करने में भी सहायक साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत के समावेशी विकास, कुल निर्यात, निर्यात में बढ़ोत्तरी, भारत के हरित विकास व आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कुमार अखिलेश(2020): ने अपने शोध अध्ययन भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति व चुनौतियां एक अध्ययन में पाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रही है। यह लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। कृषि के बाद यह दूसरा क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करता है। इसके अलावे यह आय में वृद्धि के साथ-साथ आय वितरण की असमानताओं को कम करती है जो पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है।

लाल लखन(2021): ने अपने शोध अध्ययन भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की समस्याओं और संभावनाओं का एक अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एमएसएमई जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके अलावे स्वरोजगार व रोजगार के अन्य अवसरों को सृजित करने की दिशा में यह कृषि के बाद दूसरा स्थान रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी यह मददगार साबित हो रहा है।

शोध प्रविधि

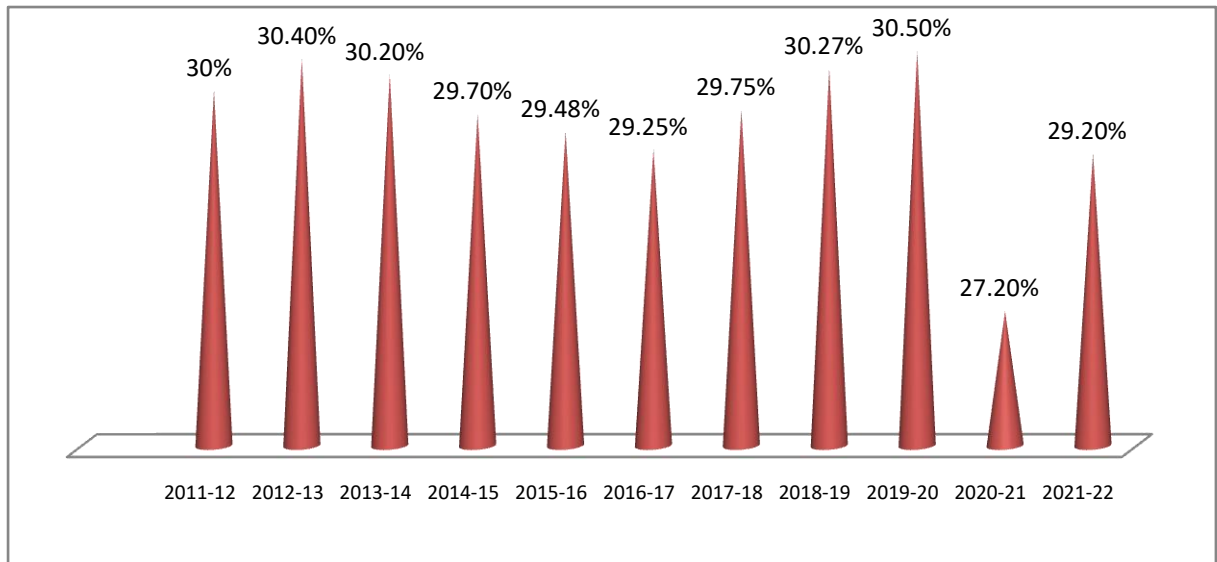
प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक, एमएसएमई मंत्रालय, सिल्क बोर्ड, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षणों, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित शोध पत्रों, विभिन्न पत्रिकाओं, सामाचार पत्रों में प्रकाशित आलोखों आदि से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र एमएसएमई के विकास का पैटर्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदानों, भारत के विदेशी व्यापार में एमएसएमई के योगदानों, भारत के कुल रोजगार में एमएसएमई के योगदानों का अध्ययन करता है।

आंकड़ों का विश्लेषण :-

तालिका-1

वर्ष	भारत की जीडीपी (बिलियन डॉलर में)	भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान(प्रतिशत में)
2011-12	1827.64	30%
2012-13	1856.72	30.40%
2013-14	2039.13	30.20%
2014-15	2103.2	29.70%
2015-16	2294.80	29.48%
2016-17	2651.47	29.25%
2017-18	2702.93	29.75%
2018-19	2835.61	30.27%
2019-20	2671.60	30.5%
2020-21	3150.31	27.2%
2021-22	3385.09	29.2%

(Source: Economic survey 2022-23)



चार्ट :-1

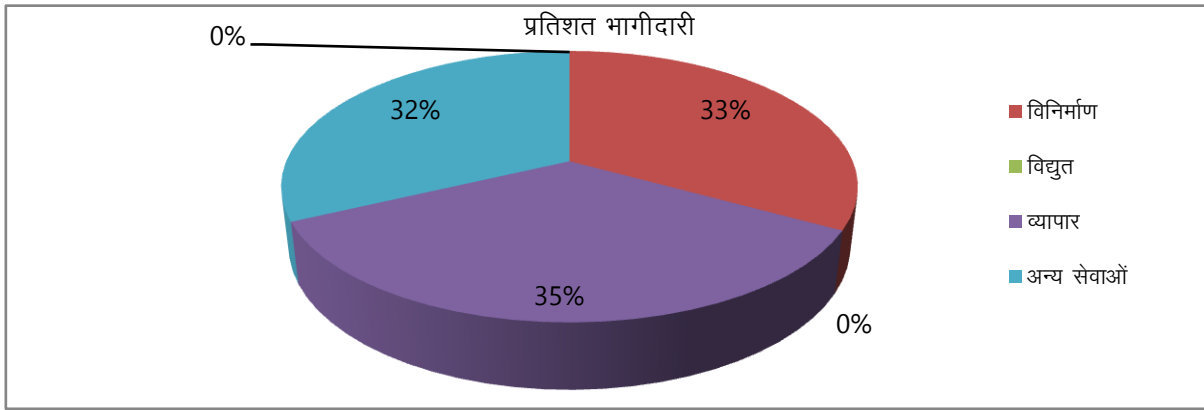
रोजगार में एमएसएमई का योगदान:-

NSS के 73 वें दौर की गणना के हिसाब से एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11 करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। एमएसएमई के भीतर तीन उपक्षेत्रों से प्रत्येक व्यापार, विनिर्माण और अन्य सेवाओं में कुल रोजगार का एक तिहाई रोजगार उत्पन्न कर रहा है। कुल एमएसएमई का 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है जो कुल एमएसएमई के तहत रोजगार का 45 प्रतिशत रोजगार उत्पन्न करता है।

तालिका-2

क्रियाविधि की श्रेणी	रोजगार (लाख में)			प्रतिशत भागीदारी
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	33%
विद्युत	0.06	0.02	0.07	0%
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35%
अन्य सेवाओं	150.53	211.69	362.22	32%
कुल	497.78	612.10	1109.89	100%

(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)



चार्ट-2

तालिका-2 और चार्ट-2 से यह स्पष्ट है कि एमएसएमई के तहत उत्पन्न कुल रोजगार में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार का 35 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा अन्य सेवाओं की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। वहीं एमएसएमई के तहत कुल 11 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं एमएसएमई के तहत उत्पन्न कुल रोजगार का 97 प्रतिशत रोजगार सिर्फ सूक्ष्म उद्यमों का रहा है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार उत्पन्न करने के दृष्टिकोण भी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

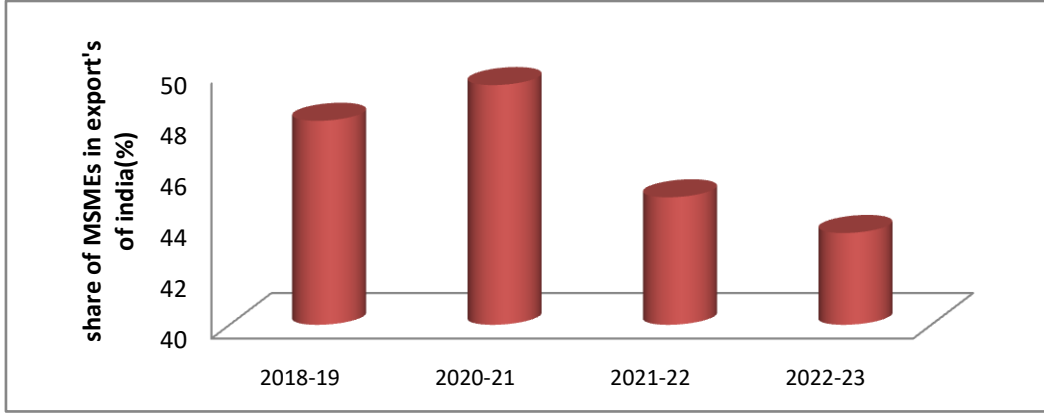
एमएसएमई का विदेशी व्यापार में योगदान :-

एमएसएमई का विदेशी व्यापार में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हलांकि कोविड काल में भारत के कुल विदेशी व्यापार में एमएसएमई के योगदान में कुछ गिरावट देखने को मिली है। विगत तीन वर्षों में भारत के कुल विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को तालिका-3 और चार्ट-3 में प्रदर्शित किया गया है :-

तालिका-3

वित्तीय वर्ष	कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान
2018-19	48%
2020-21	49.40%
2021-22	45%
2022-23	43.6%
कुल	100%

(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, 2018-19, 2019-20)



चार्ट-3

चार्ट-3 से यह स्पष्ट होता है कि भारत के कुल विदेशी व्यापार में एमएसएमई को योगदान वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात का 48 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात का 49.4 प्रतिशत, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात को 45 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल विदेशी व्यापार का 43.6 प्रतिशत एमएसएमई का योगदान रहा है। अतः भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, वर्तमान में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग एक काफी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं :-

1. वर्तमान समय में विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं जो दिन-प्रतिदिन उनकी व्यावसायिक कार्यों को बाधित करने के साथ उसकी भविष्य की संभावनाओं पर भी रोक लगा रही है।
2. इन उद्योगों में आज भी अधिकतर उद्यम अपनी पुरानी तकनीक के सहारे ही उत्पादन कर रही है जबकि वैश्विक व्यापार के दृष्टिगत एमएसएमई के छोटे आकार और उत्पादन, डिजाइनिंग, पैकेजिंग आदि की पुरानी तकनीक, विपणन की सुविधाओं की कमी के कारण बदलते परिवेश में यह प्रतिस्पर्द्धी नहीं हो पा रहे हैं।
3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एमएसएमई वृहत पैमाने पर वृहत उद्योगों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं फिर भी विनिर्माण गतिविधियों में लगे 44 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र के 27 प्रतिशत एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है।
4. सूक्ष्म और लघु उद्योगों में लगे कामगारों की आय प्रायः निम्न होती है, उनके पास पूंजी का आभाव है जिसके कारण वे आधुनिक यंत्रों की खरीद नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी वे यदि ब्याज पर उधारी लेना होता है, फलस्वरूप कर्जदारों से तकादा के कारण वे अपनी समानों को कम कीमत पर ही बेचने को विवश हो जाते हैं।
5. एमएसएमई के तहत उद्योगों को उत्पादन के लिए कच्चे माल की समस्या से भी दो चार होना होता है। एमएसएमई प्रायः अपने क्षेत्रीय इलाकों से ही कच्चे माल की खरीद करने में सक्षम होते हैं, विभिन्न प्रकार की अनिश्चिताओं के कारण उत्तम कच्चा माल और समय पर पर्याप्त कच्चे माल नहीं मिल पाता है जिससे उसका उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव होता है।
6. एमएसएमई के तहत कार्य करनेवाले उद्योगों को लागातार महंगाई के कारण अधिक लागत वहन करना होता है जिससे इसके उत्पाद अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद की कीमत से अधिक हो जाते हैं जो इसकी बिक्री को प्रभावित करते हैं
7. वहीं अन्य तरफ स्थानीय स्तर पर रंगदारी, कारीगरों का कम पढ़ा-लिख होना, पर्याप्त प्रशिक्षण का आभाव, और विभिन्न प्रकार की कर संबंधी समस्याओं के कारण इसका उत्पादन व विकास प्रभावित होता है।

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव :-

अतः उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की जीडीपी के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग कुल जीडीपी का एक तिहाई रहा है। वहीं जापान और चीन जैसे देशों में उसकी कुल जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 55 प्रतिशत और 60 प्रतिशत रहा है। अन्य उच्च प्रतिव्यक्ति आय वाले देशों की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक रहा है। वहीं भारत के कुल उत्पन्न रोजगार का 45 प्रतिशत से अधिक रोजगार एमएसएमई उत्पन्न कर रहा है। जबकि देश के कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत योगदान एमएसएमई का ही रहा है। हलांकि विगत तीन वर्षों में भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई के योगदान में गिरावट आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र की कई समस्याएँ हैं जिसका सामना एमएसएमई क्षेत्र कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर पर और स्थानीय स्तर पर वित्त व्यवस्था, वित्तीय प्रोत्साहन, नवीन तकनीक की जानकारी प्रदान करने के साथ उत्पादन की नवीन तकनीक उपलब्ध कराना, विपणन की व्यवस्था करना, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना, कम ब्याज की दरों और आसान शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके अलावे स्थानीय स्तर पर असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। भारत सरकार भी अगले कुछ वर्षों में भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई के योगदानों को बढ़ाने, एमएसएमई के नवीन उत्पादकों को प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान करना, भारत की जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को 50 प्रतिशत तक लाने की दिशा में काम कर रही है। यह तभी संभव होगा जब एमएसएमई की विभिन्न समस्याओं पर सरकारी स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सामाधान किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- [1]. SHARMA JYOTI(2016), MSME- *An Emerging Pillar of Indian Economy*, *International Journal of Research in Humanities & Soc. Sciences*, Vol. 4, Issue: 5, July:2016, p.p.16-27.
- [2]. Nagaraju et. al(2019), *The Contribution of MSMEs to the Growth of the Indian and Global Economy*, *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, Volume-04, Issue-03 , p.p. 254-263.
- [3]. Mukherjee, S. (2018), *Challenges to Indian micro small scale and medium enterprises in the era of globalization*. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 8(28), 1-19.
- [4]. Naser, A. (2013), *A critical evaluation of the contributions made by the micro, small and medium enterprises in Indian economy*. *International Journal of Marketing, Financial Services and Management Research*, 2(7), 151-158.
- [5]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2008), MSME Annual Report 2007-08.
- [6]. <https://www.msme.gov.in/sites/default/files/MSME%20ANNUAL%20REPORT%202007-08>
- [7]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2009), MSME Annual Report 2008-09.
- [8]. Srinivas(2013), Role of micro, small and medium enterprises in inclusive growth. *International Journal of Engineering and Management Research*, 3, 57-61.
- [9]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2011), MSME Annual Report 2010-11.
- [10]. https://www.msme.gov.in/sites/default/files/MSME-Annual-Report-2010-11-English_0.p
- [11]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2015), MSME Annual Report 2014-15
- [12]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2017), MSME Annual Report 2016-17.
- [13]. <https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME%20ANNUAL%20REPORT%202016-17%20ENGLISH.pdf>.
- [14]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, *Indian MSMEs Marching Ahead: Achievements 2014-18*.
- [15]. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2019), MSME Annual Report 2018-19.
- [16]. Reserve Bank of India. (2017), *Handbook of Statistics on the Indian Economy 2016-17*.
- [17]. Reserve Bank of India. (2019), *Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises*.